Nesus between FPS and black mwketeets

2041. SHRI AMAR SINGH: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that diversion of foodgrains from Fair Price Shops to open market and nexus between FPS owners and black marketeers is ram- pant in various parts of the country.

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have consti tuted any machinery to curb such activi ties;

(d) if so, the details thereof; and

(e) the number of cases detedted by that machinery during current year and the penalty imposed on FPS oowners foimd guilty of the malpractice?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CONSUMER AFFAIRS (SHRI RAGHUBANS PRASAD SINGH): (a) and (b) Public I istribution System (PDS) is implemented under the joint responsibility of Central and State Governments. While theJ Cenral Government is responsible for procuring and making available the essential commodities in bulk to States. The responsibility for their distribution lies with the respective State Government. Diversion of fobdgrainS from fair price $hops to open market, if any, is detected by the State Govemment/UT Adminis-ration and necessary corrective measures taken by them. State Governments have been empowered under Essential Com-modities Act, 1955, and Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act, 1980 to take suitable measures to curb such activities.

(c) At Government of India's level there is no machinery for thg purpose.

(d) Does not arisfe.

(e) Does not arise.

चावल के केन्द्रीय पूल स्टाक के आंकड़ों में अंतर

2042. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय और भारतीय खाद्य निगम द्वारा चलाए गए चावल के केन्द्रीय पूल स्टाक से संबधिंत आंकडों में भारी अंतर हैं,

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 1400 करोड़ रूपये मूल्य के चावल के गायब होने का अंदेशा है,

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में स्टाक की जांच-पड़ताल करने और विशेष लेखपरीक्षा करने के आदेश दिए हैं, और

(घ) यदि हां, तो स्टाक की जांच-पड़ताल कब पूरी हो जाएगी ?

खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री (श्री रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) जी, हां

(ख) जी, नहीं । भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से चावल के गायब होने की परिकल्पना इस आधार पर की गई थी कि खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा भारतीय खाद्य निगम ने स्टाक संबधी स्थिति बताने के लिए जो पद्धति अपनाई थी, उस पद्धति में अंतर था । तथापि, इन विसंगतियों का समाधान किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां । सरकार ने नियंत्रक तथा महालेखापरिक्षाक द्वारा केन्द्रीय पूल के खाद्यान्न स्टाक की विशेष लेखापरीक्षा के आवेश दिए हैं ।

(घ) स्टाक लेने की प्रक्रिया और लेखापरीक्षा के सितम्बर, 1997 के अंत तक पूर्ण हो जाने की संभावना है ।

Newsitem "Wheat stodk may fall short by 2.9 MT'

2043. SHRI S. M. KRISHNA: Will the Minister of FOOD AND CONSUMER AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the newsitem captioned